प्रेषक.

30

मनोज चन्द्रन, अपर सचिव, 'उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 🖰 जुलाई, 2014

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजना ''जंगली जानवरों द्वारा महोदय.

वित्तीय वर्ष 2014–15 की आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश सं0 80/अ0मु०स०/पी०एस०/2014–15 दि0 23 अप्रैल, 2014 में दिये गये निर्देशों के आलोक में एवं उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन सरंक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के प०सं० नि0-1798/3-5(जंगली जानवर मुवावजा), दि० 17 मई, 2014 एवं प०ंस०-नि0-2050/3-5(जंगली जानवर मुवावजा), दि० 26 जून, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोनागत पक्ष की "जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जानमाल नुकसान पर क्षतिपूर्ति" योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष ₹ 200,00,000/- (₹ दो करोड़ मात्र) की धनराशि की स्वीकृति उपरोक्त पत्र में उल्लिखित अवशेष अनुग्रह धनराशि के आवंटन/व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमित/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।
- 2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वितीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वितीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वितीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
- 4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
- 5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शिर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
- 6. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी०एम०-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
- 8. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो
- 9. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमित से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

10. मॉनक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये ग दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1407270050 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

- 15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1638/XXX-1–12(25)2011, दि० 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शिर्षक 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय 09-00 जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जानमाल नुकसान पर क्षतिपूर्ति हेतु मानक मद-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।
- 3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0- 37 (P)/XXVII(4)/2014 दिनांक 08 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

(मनोज चन्द्रन) अपर सचिव

संख्या- /x-2-2014, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार(आर्डिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
- 2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोच्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
- 10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
- 11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12 प्रमारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 13. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्द्रन) अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Forest (S016)

ावंटन पत्र संख्या -

/X-2-2014-12(30)/2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1407270050

आवंटन पत्र दिनांक -09-Jul-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक

2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय

00 - जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता क

09 - जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनत

		Plan Voted	
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	20000000	20000000
	0	20000000	20000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

20000000